



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1.

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2008/भाद्र 12, 1930

No. 313]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2008/BHADRA 12, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुल्कभ्रत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जन्मादी गणराज्य से क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के आयातों पर लागू शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

फा. सं. 15/22/2008-डीजीएडी.—यतः, वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6-11-2003 की अधिसूचना सं. 14/3/2003-डीजीएडी के तहत अन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 15-12-2003 की अधिसूचना सं. 177/2003-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह अन्तिम शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए, अपने अंतिम जाँच परिणाम 15 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 14/3/2003-डीजीएडी के तहत जारी किए और दिनांक 30 अगस्त, 2004 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 84/2004-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

## 2. समीक्षा तथा जाँच की शुरुआत हेतु अनुरोध

और, यतः, ऊपर उल्लिखित अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, लागू किए जाने की तरीखा से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा द्वारा यह निर्धारित न करें कि शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी ।

और, यतः, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, घरेलू उद्योग अर्थात् इप्का लेबोरेटरीज प्रा. लि., मुम्बई ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से ऐसी समीक्षा का अनुरोध करते हुए, एक आवेदन के साथ सम्पर्क किया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही की शुरुआत इस बात की जाँच करने के लिए उचित होगी कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा क्षति को जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की सम्भावना है ।

### 3. समीक्षा के आधार

समीक्षा हेतु आवेदक ने अनुरोध किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है क्योंकि इस उपाय की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग (आवेदक) के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया है। जो कंपनी घाटे में चल रही थी उसे जाँच अवधि के दौरान लाभ हुआ है।

### 4. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एक कार्बनिक रसायन है और इसका उपयोग मुख्यतः मलेरिया हेतु दवाई के रूप में किया जाता है। यह श्वेत अथवा लगभग श्वेत खादर चूर्ण है जो आद्रताग्राही, पानी में आसानी से घुलनशील तथा एल्कोहल, ईथर और मेथनॉल में अंशतः घुलनशील है। इसमें एन्हाइड्रस पदार्थ के संबंध में परिकलित एन 4(7-क्लोरोक्विनोलीन-4-वाई1)-एन1, N1-डाईइथाइलपेंटेन-1, 4-डाईमाइनेबिस (डाई-हाइड्रोजन फॉस्फेट) शामिल है जो 98.5% से कम नहीं है तथा 101.0% के समतुल्य से अधिक नहीं है।

क्लोरोक्वीन फॉस्फेट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 की सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 293921 तथा आईटीसी (एचएस) कोड 29392140 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा मौजूदा जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### 5. निर्यात के देश में सामान्य मूल्य

आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और इस देश से संबद्ध सभी जाँचों में इस प्राधिकारी सहित अनेक क्षेत्राधिकारों में इसे ऐसा ही माना गया है, जो अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उक्त अवधारणा के खंडन के अध्यधीन है और इसलिए इसे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार इसी रूप को माना जाना चाहिए। आवेदकों ने प्राधिकारी का ध्यानाकर्षण इस ओर भी किया है कि भारत विश्व में संबद्ध वस्तु का प्रमुख उपभोक्ता होने तथा चीन के संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक होने के कारण अनुबंध I के पैरा 7 के पहले परन्तुक के अनुसार संबद्ध देश हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई भी समरूप देश नहीं है और इसलिए संबद्ध देश हेतु सामान्य मूल्य उक्त नियमावली के दूसरे परन्तुक के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, निर्यातक देश की सरकार, संबद्ध देश के निर्यातक तथा उत्पादक संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हुए प्रस्तावली का अलग-अलग उत्तर दायर कर सकते हैं।

### 6. प्रक्रिया

(क) शामिल देश : मौजूदा समीक्षा में शामिल देश चीन जन. गण. है।

- (ख) जांच अवधि : वर्तमान जांच हेतु अवधि 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी।
- (ग) जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति पर पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और पाटन तथा क्षति की मरपाई के लिए अपेक्षित शुल्क की राशि क्या होगी।
- (घ) समीक्षा में दिनांक 15 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 14/3/2003-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे,
- (ङ) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।
- (च) सूचना प्रस्तुत करना : संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी संस्कार, भारत में उत्पाद से आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वर्णिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।

(छ) समय सीमा : वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(ज) अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपर्युक्त समझते हों।

(अ) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण : नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

(ब) उपलब्ध तथ्यों का उपयोग : जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2008

(Sunset Review)

**Subject : Initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed against import of Chloroquine Phosphate originating in or exported from China PR.**

**F. No. 15/22/2008-DGAD.**—Whereas, the Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules) recommended imposition of provisional duty vide notification No.14/3/2003-DGAD dated 6.11.2003 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Notification No.177/2003-Customs dated 15.12.2003. The Authority issued its final findings recommending imposition of definitive anti dumping duty on imports of Chloroquine Phosphate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, vide notification Number 14/3/2003-DGAD dated 15 July 2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. Of India vide customs notification No.84/2004-Customs dated 30<sup>th</sup> August, 2004.

## 2. Request for Review and Initiation

AND WHEREAS in terms of the Act and Rules referred to above the anti dumping duty imposed shall cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition unless the Designated Authority in a review determines that expiry of the duty shall lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

AND WHEREAS in terms of the above provisions, the domestic industry i.e. Ipca Laboratories Ltd., Mumbai approached the Designated Authority with an application requesting for such a review. The Authority considers that initiation of Sunset Review proceedings for the anti dumping duty in force would be appropriate to examine whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

### 3. Grounds for review

The applicant for the review has submitted that continuation of the anti dumping duties in force is warranted as expiry of the measures is likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The information as furnished by the applicant shows that financial performance of domestic industry (applicant) has improved during the injury period. The company which was incurring losses have turned to profits in the POI.

### 4. Product under consideration

The product under consideration in the present petition is Chloroquine Phosphate. Chloroquine phosphate is an organic chemical and primarily used as drug for malaria. It is a white or almost white crystalline powder, hygroscopic, freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, ether and methanol. It contains not less than 98.5% and not more than equivalent to 101.0%  $N(7\text{-chloroquinolin-4-yl})\text{-N}1, \text{N}1\text{-diethylpentane-1,4-diaminebis(di-hydrogen phosphate)}$  calculated with reference to the anhydrous substance.

Chloroquine Phosphate is classified under Customs sub-heading no.293921 of chapter 29 of the Customs Tariff act, 1975 and ITC (HS) code 29392140. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

### 5. Normal value in the country of export

The applicants have submitted that China PR continues as a non market economy country and have been treated so in several jurisdictions, including this Authority in all investigations concerning this country subject to rebuttal of the presumption by individual exporters and therefore should be treated so in terms of para 8 of the annexure i to the Rules. The applicants have also brought to the notice of the Authority that India being the major consumer of the subject goods in the world and China being the major producer of the subject goods, there is no analogous country for determination of normal value for the subject country in terms of first proviso of para 7 of annexure i and therefore the normal value for the subject country should be determined in terms of the second proviso of the said rules.

In terms of the above provisions the government of the exporting country, exporters and producers from the subject country may file separate questionnaire response rebutting the above presumption of non market economy status for determination of normal value in the subject country.

3310 07/08-2

## 6. Procedure

- a) **Countries involved:** the country involved in the present review is the Peoples Republic of China.
- b) **Period of investigation:** the period of investigation for the purpose of the present investigations is 1<sup>st</sup> April 2007 to 31<sup>st</sup> March 2008. The injury investigation period would however cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the POI.
- c) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury and the quantum of duty required for offsetting dumping and injury.
- d) The review will cover all aspects of Notification No.14/3/2003-DGAD dated 15<sup>th</sup> July 2004.
- e) The provisions of Rules 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
- f) **Submission of information** The exporters in the subject country, the governments of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the authority at the following address:

**Designated Authority**

**(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)**

**Government of India**

**Ministry of Commerce & Industry**

**Department of Commerce**

**Room No.240, Udyog Bhawan**

**New Delhi-110 011.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

- g) **Time limit** – Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the authority at the address mention above not later than forty days(40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
- h) **Submission of information on Non confidential basis** – in terms of rule 6(7) of the Rules the interested parties are required to submit non confidential summary or any confidential information provided to the authority and if in the opinion of the party providing such information such information is not susceptible to summarization a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impede the investigation the Authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the central government as deemed fit.

- i) **Inspection of public file:** in terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
- j) **Use of the facts available:** in case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation the Authority may record its findings on the basis of facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority